द्वारा सेवित क्षेत्र में 224 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं।

(ख) और (ग) ओखला गांव और उसके निकटतम पड़ौसी गांवों में 5 सार्वजनिक टेलीफोन घर कार्यरत हैं जो फिलहाल पर्याप्त हैं। इस क्षेत्र में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शीघ्र ही दो और सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

फ्रेंचाइज योजना के अंतर्गत स्थानीय, एस टी डी/आई एस डी युक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति को उदार बनाया गया है। इनके लिए प्राप्त आवेदन-पत्र, तकनीकी व्यवहार्यता और विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति के अध्यधीन उदारता से मंजूर किए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट

*218. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्टों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन ओवरड्राफ्टों की वसूली के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शान्ता राम पोट वुखे :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्यों के ओवरड्राफ्ट के बारे में नवीनतम उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

राज्य	9-5-1992 की स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट की राशि
1. असम	22.49 (तीसरे दिन)
2. गुजरात	126.23 (छठे दिन)
3. हिमाचल प्रदेश	15.42 (पांचवें दिन)
4. केरल	98.79 (पांचवें दिन)
5. मध्य प्रदेश	108.97 (पांचवें दिन)
6. मणिपुर	2.87 (दूसरे दिन)
7. मिजोरम	0.33 (पहले दिन)
8. उड़ीसा	9.68 (दूसरे दिन)
9 त्रिपुरा	12.12 (छठे दिन)
10 पश्चिम बंगाल	3.68 (दूसरे दिन)

(ख) और (ग) यह राज्य सरकारों का काम है कि वे ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम में निर्धारित किए गए अनुसार अपने ओवरड्राफ्ट सात क्रमिक कार्य दिवसों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने हेतु कदम उठाएं।

भारत में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विदेशी संस्थानों को सहायता

*219. **सरदार जगजीत सिंह अरीड़ा :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या विद्युत और गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी संस्थानों को देश की विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारतीय वित्तीय संस्थाओं से 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी;